1	2	3	4	5	6
6.	खान . . .	0	0.0	0.0	0.0
7.	इस्पात और खनिज लोहा .	5	6139.2	15069.7	8930.5
8.	रसायन तथा पट्रो रसायन .	3	1294.9	1844.2	549.3
9.	पैट्रो तथा प्राकृतिक गैस .	17	3681.6	4664.4	982.8
10.	विद्युत . . .	32	14453.7	26571.5	12117.8
11.	उद्योग (कागज, सिमेंट तथा आटो इत्यादि) . . .	6	762.1	1393.0	630.9
12.	रेलवे . . .	44	2247.6	5428.2	3180.6
13.	भूतल परिवहन . .	21	1663.4	2726.1	1062.7
14.	दूर संचार . .	16	603.6	729.0	125.4
	कुल . . .	189	37889.4	73608.5	35719

Number of Projects identified for Completion

1740. SHRI RANJIT SINGH:
DR. JINENDRA KUMAR JAIN:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in "The Hindu" of 19th December, 1991 under the caption "On going projects for nearly Rs. 4,00,000 crore";

(b) if so, the total number of projects that have been identified for completion in the forthcoming years;

(c) what are the estimates about the periods and the amount of money required for completion of these projects;

(d) whether special measures and vigilance is being undertaken by Government to complete these projects within the targetted period; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir. The news item to which the Hon'ble Member has drawn attention relates to investment costs of all on-going projects in Central States, Joint Sector and private Sectors. As per this sources, nearly 60 per cent relates to on-going projects of the Public Sector, of which Central Sector accounts for 33.2 per cent and State Sector accounts for 26.6 per cent.

(b) and (c) As per the monitoring system of Department of Programme Implementation, as on 31st December 1991, there were 307 Central projects each costing over Rs. 20 crores under implementation in 14 sectors of the economy. The anticipated cost of completion of these projects is Rs. 94511.5 crores. Of these, 273 projects are anticipated to be completed by November, 1999. The date of completion of the remaining 34 projects is yet to be firmed up.

(d) and (e) Yes, Sir. Besides the close monitoring of these projects by the concerned Administrative Ministries|Departments these projects are

also monitored by Ministry of Planning and Programme Implementation. A task force under the Chairmanship of the Secretary, Planning Commission has also been constituted to expedite the completion of the projects in power and coal sectors. The Committee of Secretaries has also been reviewing the progress of these projects from time to time to resolve the problems faced by them.

1741. [*Transferred to the 13th March, 1992*].

क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए जारी किए गए निदेश

1742. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने योजना आयोग को क्षेत्रीय आर्थिक विषमताओं और सामाजिक दमन को कम करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों में समस्त देश के खनिज भण्डारों के कितने प्रतिशत खनिज भण्डार हैं, प्रमुख खनिजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और विभिन्न योजनाओं द्वारा उनके समुचित उपयोग के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितना खर्च आने की संभावना है और बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और मध्यप्रदेश के राज्यों पर कुल खर्च में से प्रत्येक राज्य पर कितने-कितने प्रतिशत खर्च किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार गाडगिल फार्मूले को रद्द करने का विचार कर रही है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलनों में कमी तथा सामाजिक दबाव किसी हद तक सरकार तथा योजना आयोग की आयोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

(ख) सभी राज्यों में खनिज-वार भण्डारों का अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक राज्य में काफी संख्या में बड़े और छोटे खनिज हैं जो सम्भावना और महत्ता में अलग-अलग होते हैं और अतः राज्य का अंशदान सामान्यतः खनिज उत्पादन के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसाकि भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका (आईएमवाईबी) में दर्शाया गया है।

बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों का अंशदान (परमाणु खनिजों को छोड़कर) नीचे दिया है जैसाकि 1988 में खनिज उत्पादन के मूल्य पर आधारित भारतीय खनिज वर्ष पुस्तिका 1991 में दर्शाया गया है :—

राज्य	खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड़ रु० में)	प्रतिशत अंशदान
भारत	14272	100
बिहार	2057	14.41
पश्चिम बंगाल	706	4.95
मध्य प्रदेश	1493	10.47
उड़ीसा	468	3.28